माननीय जी.आर. मजीठिया और आर.के. नेहरू, जे.जे, के समक्ष

देविंदर कुमार और अन्य, - अपीलकर्ता।

बनाम

सिंडिकेट बैंक और अन्य,-प्रतिवादी,

आर.एस.ए. 1989 का क्रमांक 2665

4 जून 1993

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - धारा 34 - ब्याज - मूल राशि का अर्थ उधार दी गई मूल राशि - मूल राशि पर देय ब्याज लंबित - लेकिन मूल राशि पर देय ब्याज पर कोई ब्याज देय नहीं है।

अभिनिर्णीत, कि अभिव्यक्ति "मूल राशि" का अर्थ है बिना किसी ब्याज के उधार दी गई मूल राशि। अदालत, मुकदमे पर डिक्री सुनाते समय (i) मूल राशि और (ii) मुकदमे की शुरुआत की तारीख से पहले ऐसी मूल राशि पर कोई ब्याज तय करेगी। मुकदमे की स्थापना से पहले की अवधि के लिए न्यायालय द्वारा "मूल राशि" के साथ-साथ उस पर "ब्याज" के रूप में तय की गई दोनों राशियों को मुकदमे की तारीख पर देय "कुल न्यायनिहित राशि" कहा जा सकता है। लेकिन संहिता की धारा 34 के तहत ऐसी कुल राशि पर ब्याज देय नहीं है।

(पैरा 11 एवं 21)

आगे निर्धारित किया गया है कि, तय की गई मूल राशि पर ब्याज लंबित है, लेकिन ऐसी मूल राशि पर तय ब्याज की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(पैरा 21)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) एस. 34- भविष्य में ब्याज संविदात्मक ब्याज दर पर दिया जाएगा और यदि ऐसी कोई दर स्थापित नहीं है तो उसी दर पर जिस पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वाणिज्यिक लेनदेन के लिए पैसा उधार दिया जाता है।

निर्धारित किया कि भविष्य का ब्याज ब्याज की संविदात्मक दर पर दिया जाएगा और यदि ब्याज की संविदात्मक दर स्थापित नहीं है, तो उस दर पर जिस पर वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पैसा उधार दिया जाता है या अग्रिम दिया जाता है।

(पैरा 11)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 39 नियम 2, 11 - आदेश 39 नियम 2 के खंड (ए) और (बी) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि मूलधन और ब्याज को अलग-अलग तय किया गया है - नियम 11 के किसी भी खंड के तहत ब्याज केवल मूल राशि पर दिया जा सकता है - मुकदमा दायर करने की तारीख से पहले देय ब्याज को मूल राशि के रूप में नहीं माना जाएगा।

माना गया कि आदेश 34 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ए) और (बी) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि "प्रिंसिपल" और "ब्याज" को अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस प्रकार देय घोषित किया जाना चाहिए। नियम 2 मूलधन में ब्याज के विलय और दोनों के कारण देय कुल राशि के निर्धारण पर विचार नहीं करता है।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया कि संहिता के आदेश 34 के नियम 11(ए)(i) के तहत ब्याज "बंधक पर पाई गई या घोषित मूल राशि" पर देय है। नियम 11(ए) के उप-खंड (iii) के तहत, प्रारंभिक डिक्री की तारीख तक लागत, शुल्क और व्यय के लिए गिरवीदार को देय राशि पर भी ऐसा ब्याज देय होता है और बंधक धन में जोड़ा जाता है। इस प्रकार न्यायालय को "ब्याज" को छोड़कर वादी को देय राशि के सभी घटकों पर नियम 11(ए) के तहत ब्याज देने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार, वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक बाद का ब्याज भी नियम 11 (बी) के तहत केवल "खंड (ए) में निर्दिष्ट मूल राशि के कुल" पर दिया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 11 के दोनों खंडों में से किसी एक के तहत ब्याज केवल मूलधन पर दिया जा सकता है। मुकदमा दायर करने की तारीख से पहले देय ब्याज को मूलधन नहीं माना जाता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि वादी को देय ब्याज की राशि अलग से निर्धारित की जानी है।

(पैरा)

याचिकाकर्ताओं की ओर से बी.एस. राणा, अधिवक्ता, एस.के.मित्तल, अधिवक्ता।

ए.के.जायसवाल. प्रतिवादी संख्या 1 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) यह नियमित दूसरी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जो वादी-प्रतिवादी के मुकदमे पर फैसला सुनाने वाले ट्रायल जज के फैसले की अपील पर पुष्टि करती है। बैंक को मुकदमे की तारीख से डिक्रीटल राशि की वसूली तक 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज के साथ 93,377-39 रुपये की वसूली के लिए।

(2) तथ्य प्रथम:-

सिंडिकेट बैंक, रेवाडी शाखा (इसके बाद वादी-बैंक) ने साझेदारी संस्था मेसर्स सप्रा टेक्सटाइल एजेंसी, केवलबाजार, रेवाडी को ओवरड्राफ्ट ऋण सुविधा की अनुमति दी। सर्वश्री जगदीश चंदर, देवेन्द्र कुमार और श्रीमती दया वंती फर्म के भागीदार थे। वादी-बैंक द्वारा उन्हें 12 जनवरी, 1977 को 50,000 रुपये का ऋण दिया गया था और साझेदारों ने वादी-बैंक, सर्वश्री जगदीश चंदर और देविंदर कुमार के पिता और श्रीमती के पति श्री शाम दास के पक्ष में प्रोनोट, सुरक्षा बांड, समझौते का बंधक और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज निष्पादित किए। दया वंती ने सह-दायित्व के रूप में स्वामित्व विलेख जमा करके रेवाडी स्थित अपनी संपत्ति क्रमांक ईपी-403/156.1 को गिरवी रख दिया। मेसर्स सप्रा टेक्सटाइल एजेंसी के साझेदारों ने भी ओवरड्राफ्ट ऋण सुविधाओं के बदले अपने स्टॉक-इन-ट्रेड को गिरवी रख दिया, जिसमें सभी प्रकार के कपड़ा सामान शामिल थे। देनदारों द्वारा 10 जनवरी 1980 को ऋण स्वीकार किया गया था। ऋण का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण 5 दिसंबर 1980 को 93,377-39 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना आवश्यक हो गया।

(3) वादपत्र के मुख्य भाग में यह नहीं बताया गया है कि मूल राशि क्या है और 93,377.39 रुपये की देनदारी कैसे बनाई गई । यह मुकदमा मेसर्स सपरा टेक्सटाइल एजेंसी, उसके साझेदारों और सह-बाध्यकारी श्री शाम दास सपरा, श्री शाम दास सपरा, श्री जगदीश चंदर के पिता और श्रीमती दया वंती के पति, अपीलकर्ताओं द्वारा लड़ा गया था, जो कि ऋण पुनर्भुगतान के लिए जमानत पर खड़े थे। उन्हें सामूहिक रूप से प्रतिवादी कहा जाता है।

(4) पार्टियों की दलीलों से, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

(1) क्या श्री के. वी. सिरिनिवासन अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने और वादी बैंक की ओर से यह मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत हैं? ओपीपी.

(2) क्या वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में पचास हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है? ऑप

(3) क्या प्रतिवादी संख्या 5 उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सह-देनदार था, जैसा कि आरोप लगाया गया है? ऑप

(4) क्या प्रतिवादी संख्या 5 ने अपनी रेवारी स्थित संपत्ति संख्या 403/1561 को वादी बैंक के पक्ष में गिरवी रख दिया, जैसा कि आरोप लगाया गया है, यदि हां, तो किस प्रभाव से? ऑप

(5) वादी प्रतिवादियों से मूलधन के रूप में कितनी राशि और ब्याज के रूप में कितनी राशि वसूलने का हकदार है। ओपीडी.

(6) क्या वादी का वाद समयान्तर्गत है? ऑप

(7) अनुतोष

(5) मुद्दा क्रमांक 1 के अंतर्गत, यह निर्धारित किया गया कि मुकदमा एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था और इस मुद्दे को तदनुसार वादी-बैंक के पक्ष में तय किया गया था, मुद्दा संख्या 2, 3 और 4 का एक साथ निपटारा किया गया था और यह यह निर्धारित किया गया कि मेसर्स सप्रा टेक्सटाइल एजेंसी और उसके साझेदारों को 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ 50,000 रुपये का ऋण दिया गया था, अर्थात्,सर्वश्री जगदीश चंदर, देविंदर कुमार और श्रीमती दयावंती, और श्री शाम दास सपरा उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सह-ऋणी के रूप में खड़े हुए और वह उन्होंने वादी-बैंक के पक्ष में रेवाड़ी स्थित अपनी संपत्ति संख्या 403/1561 गिरवी रख दी और तदनुसार इन मुद्दों का निर्णय वादी-बैंक के पक्ष में किया गया। मुद्दा संख्या 5 के तहत, यह माना गया कि वादी-बैंक प्रतिवादियों से 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 93,377-39 रुपये की राशि वसूल करने का हकदार था। मुद्दा संख्या 6 के तहत, यह यह निर्धारित किया गया कि प्रतिवादियों ने 10 जनवरी, 1980 को पहले से मौजूद दायित्व की वैध स्वीकृति दी थी और मुकदमा सीमा के भीतर था। अंतिम विश्लेषण पर, ट्रायल कोर्ट ने वादी-बैंक के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ 93,377-39 रुपये गुप्त राशि की वसूली के लिए मुकदमा शुरू होने की तारीख से वसूली तक 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज देने का फैसला सुनाया। मेसर्स सपरा टेक्सटाइल एजेंसी के पार्टनर श्री देवेन्द्र कुमार और श्रीमती दयावंती ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को चुनौती दी। वादी-बैंक ने यह कहते हुए प्रतिवाद दायर किया कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश 34, नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं करके गलती की है। अपील श्री देवेन्द्र कुमार और श्रीमती दयावंती द्वारा दायर की गई। प्रतिवादियों को खारिज कर दिया गया और वादी-बैंक द्वारा दायर प्रति-आपत्तियों को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, - 24 मार्च 1989 के फैसले और डिक्री द्वारा। अंतिम डिक्री के बजाय, वादी के पक्ष में एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी- बैंक और उसके फैसले के पैराग्राफ 13 और 14 में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस प्रकार प्रेक्षित किया: -

"13. 14 दिसंबर, 1985 को दायर संशोधित वादपत्र से पता चलता है कि वादी बैंक ने प्रारंभिक डिक्री के लिए प्रार्थना की थी। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि घर को बैंक के पास समान रूप से गिरवी रखा गया था। अत: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 34. नियम 4 के तहत प्रारंभिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी।

तदनुसार, अंतिम डिक्री के बजाय, प्लैटिफ बैंक के पक्ष में एक प्रारंभिक डिक्री जारी की जाती है। यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए भविष्य के ब्याज सहित राशि का भुगतान छह महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो, बैंक अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए आवेदन कर सकता है और उसके बाद डिक्री पारित कर दी जाएगी।14. परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी जाती है और वादी बैंक द्वारा दायर की गई प्रति-आपत्तियाँ लागत सहित स्वीकार कर ली जाती हैं। उचित अनुपालन के बाद फ़ाइल को रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। प्रतिवादी देवेन्द्र कुमार एवं श्रीमती दयावंती प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध व्यथित होकर नियमित द्वितीय अपील में आये हैं।

(6) . जब यह अपील एकांत में बैठे हुए हमारे समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय द्वारा लंबित ब्याज केवल मूल राशि पर ही दिया जा सकता है, न कि मुकदमे में दावा की गई पूरी राशि पर। इसी प्रकार, भविष्य का ब्याज केवल मूल राशि पर ही दिया जा सकता है जैसा कि न्यायालय ने अपने फैसले और डिक्री में तय किया है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने माखन सिंह बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य[1] में इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया। इस निर्णय की सत्यता पर संदेह किया गया और अपील को डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया गया और मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को शीघ्रता से सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। इस तरह से निर्णय के लिए अपील हमारे सामने रखी गई है।

(7) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि प्रतिवादियों को 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर 50,000 रुपये का ऋण दिया गया था। वह मुकदमे में दावा किए गए 93.377-39 पी रुपये की मूल राशि और मुकदमा दायर करने से पहले उस पर अर्जित ब्याज की शुद्धता पर भी विवाद नहीं करता है। उनकी एकमात्र शिकायत यह है कि मुकदमे की सुनवाई की तारीख से डिक्रीटल राशि की वसूली तक प्रति वर्ष 19 प्रतिशत की दर से ब्याज पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज की अनुमति देने में ट्रायल जज ने गलती की थी।

(8) निर्धारण के लिए जो सटीक तर्क उठता है वह यह है कि क्या मुकदमे में दावा की गई मूल राशि पर लंबित ब्याज और भविष्य का ब्याज देने में ट्रायल जज सही थे। मुकदमे में दावा की गई राशि में 50,000 रुपये की मूल राशि पर देय चक्रवृद्धि ब्याज शामिल है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से मूल राशि और मुकदमा दायर होने तक उस पर अर्जित ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज शामिल है। उनकी एकमात्र शिकायत यह है कि ट्रायल जज ने डिक्री की तारीख से लेकर डिक्री राशि की वसूली तक प्रति वर्ष 19 प्रतिशत की दर से ब्याज पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज देने में सही नहीं थे।

(9) वादपत्र के अवलोकन से यह नहीं पता चलता कि वाद में किस आधार पर 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज का दावा किया गया था। वादी के पैरा संख्या 7 में कहा गया है कि वादी-बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादी पर 93,377-39 रुपये की राशि बकाया है। वादपत्र के पैरा 8 में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने 10 जनवरी 1980 को ऋण स्वीकार कर लिया था और मुकदमा परिसीमा के भीतर था। वादपत्र के पैरा 11 में कहा गया है कि वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध 93,377-39 रुपये की राशि के लिए 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागत और भविष्य के ब्याज के साथ एक डिक्री पारित की जाए। मुकदमा दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान तक। ऐसी कोई दलील नहीं है कि डिक्री की तारीख से लेकर वसूली तक ब्याज पेंडेंट लाइट या भविष्य का ब्याज ब्याज की संविदात्मक दर पर देय है।

(10) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में मुकदमे की तारीख से डिक्री की तारीख तक, मुकदमे की स्थापना से पहले किसी भी अवधि के लिए ऐसी मूल राशि पर दिए गए किसी भी ब्याज के अलावा, डिक्री की तारीख से

---

[1] 1999 (1) 95 P.L.R 703

भुगतान की तारीख तक, या ऐसी पहले की तारीख तक, जो न्यायालय उचित समझे, ऐसी मूल राशि पर भविष्य में ब्याज छह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा: -

"34. ब्याज.- (1) जहां तक और जहां तक डिक्री पैसे के भुगतान के लिए है, अदालत, डिक्री में, ऐसी दर पर ब्याज का आदेश दे सकती है, जिसे अदालत न्यायनिर्णित मूल राशि पर भुगतान करना उचित समझे मुकदमे की तारीख से डिक्री की तारीख तक, मुकदमे की शुरुआत से पहले किसी भी अवधि के लिए ऐसी मूल राशि पर दिए गए किसी भी ब्याज के अलावा, ऐसी दर पर अतिरिक्त ब्याज, प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि न्यायालय ऐसी मूल राशि पर उचित समझे, डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक, या ऐसी पहले की तारीख तक जो न्यायालय उचित समझे।

बशर्ते कि जहां इस प्रकार तय की गई राशि के संबंध में देनदारी किसी वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुई हो, ऐसे अतिरिक्त ब्याज की दर प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक हो सकती है, लेकिन ब्याज की संविदात्मक दर से अधिक नहीं होगी या जहां कोई संविदात्मक नहीं है दर, वह दर जिस पर वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन उधार दिया जाता है या अग्रिम दिया जाता है।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में, "राष्ट्रीयकृत बैंक" का अर्थ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 में परिभाषित एक संबंधित नया बैंक है।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक लेन-देन एक वाणिज्यिक लेन-देन है, यदि यह दायित्व वहन करने वाली पार्टी के उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा है।

(2) जहां ऐसी डिक्री डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख या अन्य पहले की तारीख तक ऐसी मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के संबंध में चुप है, तो न्यायालय ने इस तरह के ब्याज और एक अलग ब्याज से इनकार कर दिया है। इसलिए मुकदमा झूठ नहीं बोलेगा"

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के तहत दिए जाने वाले ब्याज को तीन प्रमुखों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्,

(1) मुक़दमे की शुरुआत से पहले न्यायनिर्णित मूल राशि पर अर्जित ब्याज (जैसा कि दावा की गई मूल राशि से अलग है);

(2) मुक़दमे की तारीख से डिक्री की तारीख तक निर्णय की गई मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज, 'ऐसी दर पर जो न्यायालय उचित समझे'।

(3) डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक या ऐसी पहले की तारीख तक, जिसे न्यायालय उचित समझे, प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक की दर से मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा।

मुकदमे की तारीख तक का ब्याज मूल कानून का मामला है और यह धारा पहले शीर्ष के तहत ब्याज के भुगतान का उल्लेख नहीं करती है। यह केवल दूसरे और तीसरे शीर्ष पर लागू होता है। ब्याज पेंडेंट लाइट न्यायालय के विवेक के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। संहिता की धारा 34 के पहले प्रावधान के तहत डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक मूल राशि पर ब्याज 6 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की दर से देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भविष्य में एक प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक का ब्याज तब दिया जा सकता है जब देयता वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुई हो और, किसी भी स्थिति में, यह ब्याज की संविदात्मक दर से अधिक न हो, और यदि ब्याज की संविदात्मक दर स्थापित नहीं है, न्यायालय कॉनर्मक्राई लेनदेन के संबंध में राष्ट्रीयकृत ओएएनएच द्वारा अनुमत दर पर ब्याज दे सकता है। चूँकि यह विवादित नहीं था कि पैसा एक वाणिज्यिक

लेनदेन के तहत दिया गया था, मामला पूरी तरह से नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के पहले प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा।

(11) मौजूदा मामले में, 50,000 रुपये का ऋण 12 जनवरी 1977 को दिया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (1976 का 104) को 9 सितंबर 1976 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. जारी की। 15 (ई), दिनांक 14 जनवरी 1977 जिसने 1 फरवरी 1977 को वह तारीख नियुक्त की जिस दिन धारा 12, 13 और 50 को छोड़कर नए अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और 1 मई, 1977 वह तारीख है जब धारा 12 और 50 लागू होंगी। एक अन्य अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. केंद्र सरकार द्वारा जारी 416 (ई), दिनांक 27 जून, 1977 ने 1 जुलाई, 1977 को वह तारीख तय की जब धारा 13 लागू होगी। मुकदमा 5 दिसंबर 1980 को दायर किया गया था, यानी सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976 का 104 लागू होने के बाद और 1976 के अधिनियम 104 द्वारा संशोधित धारा 34 तत्काल मुकदमे पर लागू होगी। अभिव्यक्ति "मूल राशि'' का अर्थ है बिना किसी ब्याज को जोड़े उधार दी गई मूल राशि। अदालत, मुकदमे पर फैसला सुनाते समय, (i) मूल राशि और (ii) मुकदमे की शुरुआत की तारीख से पहले ऐसी मूल राशि पर कोई ब्याज तय करेगी। मुकदमे की स्थापना से पहले की अवधि के लिए न्यायालय द्वारा "मूल राशि'* के साथ-साथ उस पर "ब्याज" के रूप में तय की गई दोनों राशियों को मुकदमे की तारीख पर देय "कुल न्यायनिहित राशि" कहा जा सकता है। लेकिन संहिता की धारा 34 के तहत ऐसी कुल राशि पर ब्याज देय नहीं है। यह केवल निर्धारित मूल राशि पर ही देय होता है। ऐसी मूल राशि पर निर्धारित ब्याज की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। ब्याज, चाहे साधारण हो या चक्रवृद्धि, धारा 34 के प्रयोजन के लिए "ब्याज" ही रहेगा और मूलधन में कभी भी विलय नहीं होगा। विधायिका अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 34 में "मुकदमा शुरू होने से पहले किसी भी अवधि के लिए ऐसे मूलधन पर तय किए गए किसी भी ब्याज के अलावा" अभिव्यक्ति "मूलधन" के विपरीत, साधारण ब्याज के माध्यम से गणना किए गए ब्याज के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है या चक्रवृद्धि ब्याज। संहिता की धारा 34 में अभिव्यक्ति मूल राशि न्यायनिर्णित" का अर्थ उधार दी गई मूल राशि है, जिसमें कोई भी ब्याज शामिल नहीं है। पार्टियों के बीच किसी समझौते या इसके विपरीत किसी प्रचलित बैंकिंग या व्यापार प्रथा के बावजूद यह स्थिति रहेगी। इसी प्रकार, आदेश का नियम 2, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रारंभिक डिक्री या "मूलधन" और "बंधक पर ब्याज" की तारीख के रूप में वादी को देय राशि का ध्यान रखना है। आदेश 34 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (बी) के तहत न्यायालय को उस तिथि पर देय राशि की घोषणा करनी होगी। आदेश 34 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ए) और (बी) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि "मूलधन" और "ब्याज" को अलग-अलग सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस तरह देय घोषित किया जाना चाहिए। नियम 2 मूलधन में ब्याज के विलय और दोनों की राशि पर देय कुल राशि के निर्धारण पर विचार नहीं करता है। संहिता के आदेश 34 के नियम 11 (ए) (i) के तहत ब्याज "बंधक पर पाई गई या घोषित मूल राशि" पर देय है। आदेश 34 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (बी) के तहत न्यायालय को उस तिथि पर देय राशि की घोषणा करनी होगी। आदेश 34 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ए) और (बी) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि "मूलधन" और "ब्याज" को अलग-अलग सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस तरह देय घोषित किया जाना चाहिए। नियम 2 मूलधन में ब्याज के विलय और दोनों की राशि पर देय कुल राशि के निर्धारण पर विचार नहीं करता है। संहिता के आदेश 34 के नियम 11 (ए) (i) के तहत ब्याज "बंधक पर पाई गई या घोषित मूल राशि" पर देय है। नियम 11 (ए) के उप-खंड (iii) के तहत, प्रारंभिक डिक्री की तारीख तक लागत, शुल्क और व्यय के लिए गिरवीदार के कारण तय की गई राशि पर और बंधक धन में जोड़े जाने पर भी ऐसा ब्याज देय होता है। इस प्रकार न्यायालय को "ब्याज" को छोड़कर वादी को देय राशि के सभी घटकों पर नियम आईटी (ए) के तहत ब्याज देने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार, वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक बाद का ब्याज भी नियम 11 (बी) के तहत केवल "खंड (ए) में निर्दिष्ट मूल राशि के कुल" पर दिया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 11 के दोनों खंडों में से किसी एक के तहत ब्याज केवल मूलधन

पर दिया जा सकता है। मुकदमा दायर करने की तारीख से पहले देय ब्याज को मूलधन नहीं माना जाता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि वादी को देय ब्याज की राशि अलग से निर्धारित की जानी है।

(12) यह सटीक प्रश्न यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम गौरीशंकर उपाध्याय[2] मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए उठा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, खंडपीठ ने इस प्रकार प्रेक्षित किया: -

आरए स्पष्ट तस्वीर जो इस खंड को पढ़ने से उभरती है वह यह है कि अदालत मुकदमे का फैसला करते समय, (i) मूल राशि और (ii) मुकदमे की स्थापना की तारीख से पहले ऐसी मूल राशि पर कोई ब्याज तय करेगी। न्यायालय द्वारा "मूल राशि" के साथ-साथ "मुकदमे की शुरुआत से पहले की अवधि के लिए उस पर ब्याज" के रूप में तय की गई दोनों राशियों को मुकदमे की तारीख पर देय "कुल न्यायनिहित राशि" कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी कुल राशि पर धारा 34 के तहत ब्याज देय नहीं है। टीटी को केवल मूल राशि पर देय किया जाता है। ऐसी मूल राशि पर। ब्याज, चाहे साधारण हो या चक्रवृद्धि, धारा 34 के प्रयोजन के लिए 'ब्याज' ही रहेगा और मूलधन में कभी भी विलय नहीं होगा। विधायिका अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 34 में "मुकदमे पर संस्था की स्थापना से पहले किसी भी अवधि के लिए ऐसे मूलधन पर तय किए गए ब्याज के अलावा" अभिव्यक्ति "मूलधन" के विपरीत, साधारण ब्याज के माध्यम से गणना किए गए ब्याज के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है या चक्रवृद्धि ब्याज। विधायी योजना और मंशा इतनी स्पष्ट होने के कारण, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि अभिव्यक्ति "मुख्य राशि तय" का अर्थ केवल "मुख्य राशि" होगा। इसमें पार्टियों के बीच समझौते से प्राप्त ब्याज कभी भी शामिल नहीं होगा। इसलिए, धारा 34 के तहत ब्याज केवल मूल राशि पर ही दिया जा सकता है, न कि मुकदमा दायर होने तक मूल राशि और उस पर अर्जित ब्याज पर। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा मानना है कि सी.पी.सी. की धारा 34 में प्रयुक्त "निर्णयित मूल राशि" का अर्थ है बिना किसी ब्याज को जोड़े उधार दी गई मूल राशि। पार्टियों के बीच किसी समझौते या इसके विपरीत किसी प्रचलित बैंकिंग या व्यापार प्रथा के बावजूद यह स्थिति रहेगी। पहले तीन प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(13) आदेश 34 के नियम 2 और 11, सिविल प्रक्रिया संहिता की व्याख्या बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा इस प्रकार की गई: -

"ऊपर निर्धारित नियम 2 को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय पर अन्य बातों के साथ-साथ, "प्रिंसिपल" के लिए प्रारंभिक डिक्री की तारीख पर वादी को देय राशि का ध्यान रखने का आदेश देने का कर्तव्य डालता है। और "रुचि; गिरवी पर" खंड (बी) के तहत न्यायालय को उस तिथि पर देय राशि की घोषणा करनी होगी। नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ए) और (बी) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि "मूलधन" और "ब्याज" को अलग-अलग सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस तरह देय घोषित किया जाना चाहिए। नियम 2 मूलधन में ब्याज के विलय और दोनों के कारण देय कुल राशि के निर्धारण पर विचार नहीं करता है। नियम 11 डिक्री की तारीख से भुगतान के लिए निर्धारित तिथि तक ब्याज देने का प्रावधान करता है, और उस तारीख तक भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक आगे ब्याज देने का प्रावधान करता है। नियम 11(ए)(i) के तहत ब्याज "बंधक पर पाई गई या घोषित मूल राशि" पर देय है।

उपखंड (iii) के तहत प्रारंभिक डिक्री की तारीख तक लागत, शुल्क और व्यय के लिए गिरवीदार के कारण तय की गई राशि पर और बंधक धन में जोड़े जाने पर भी ऐसा ब्याज देय है। इस प्रकार न्यायालय को "ब्याज" को छोड़कर वादी को देय राशि के सभी घटकों पर नियम 11 (ए) के तहत ब्याज देने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार, वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक बाद का ब्याज भी नियम 11 (बी) के तहत केवल "खंड (ए) में निर्दिष्ट मूल राशि के कुल" पर दिया जा सकता है। खंड (ए), जैसा कि ऊपर बताया गया है, विशेष रूप से

---

[2] **A.I.R. 1992 Bombay 482**

बंधक पर देय ब्याज को इसके दायरे से बाहर करता है। खंड (बी) में निर्दिष्ट मूल राशि का मतलब केवल बंधक पर पाई गई या घोषित की गई मूल राशि और लागत, शुल्क और व्यय के लिए बंधक के कारण तय की गई मूल राशि है। इसलिए, इनमें से किसी भी राशि पर ब्याज नियम 11 के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मूल रकम का कुल" के अंतर्गत नहीं आएगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियम 11 के दोनों खंडों में से किसी एक के तहत ब्याज केवल मूलधन पर दिया जा सकता है। मुकदमे से पहले अर्जित ब्याज को मूलधन के रूप में नहीं माना जाता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि वादी को देय ब्याज की राशि अलग से निर्धारित की जानी है [आदेश 34 का नियम 2(1) (ए) (i)]।"

(14) संहिता की धारा 34 और आदेश 34 के नियम 2 और 11 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि संहिता के आदेश 34 के धारा 34, नियम 2(1) (ए) (i) और नियम 11 (बी) में निर्दिष्ट अभिव्यक्तियाँ "निर्णित मूलधन", "मूलधन" और "मूलधन का योग" का अर्थ केवल " मूलधन" न कि "मूलधन और ब्याज"। इसके बाद ब्याज केवल मूलधन पर ही दिया जा सकता है। नियम 11 के तहत कोई ब्याज देय नहीं है।

(15) वादी-बैंक के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है। निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया: -

(1) भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स नीरू प्लास्टिक और अन्य,[3] ।

(2) मैसर्स एस.एम. एंटरप्राइजेज, फ़रीदाबाद बनाम भारतीय स्टेट बैंक, एन.आई.टी., फ़रीदाबाद,[4]।

(3) श्रीमती उषा सचदेवा और अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली,[5] ।

(4) चानन सिंह बनाम पंजाब नेशनल बैंक, चाणौर एवं अन्य,[6]

(16) सुश्री नीरू प्लास्टिक मामले में, वादी-बैंक ने गिरवी रखे गए माल की बिक्री से 25 अप्रैल, 1977 तक ब्याज सहित कैश क्रेडिट (फैक्टरी प्रकार) खाते के तहत देय राशि के कारण 93,347.10 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। मशीनरी को उपरोक्त राशि की संतुष्टि के लिए और संपत्ति की बिक्री से संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका विवरण वादपत्र में दिया गया था। ट्रायल कोर्ट निम्नलिखित शर्तों में मुकदमे का फैसला सुनाता है: -

"उपरोक्त मुद्दों पर मेरे निष्कर्षों के प्रकाश में, वादी के मुकदमे की तारीख से राशि की वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 93,347.18 रुपये का फैसला सुनाया जाता है। वादी प्रतिवादी के सामान और मशीनरी की बिक्री से, और वादी के पास संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई राशि और संपत्ति संख्या XXI-837, प्रताप नगर, लुधियाना की बिक्री से इस राशि को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। वादी के शीर्ष-नहीं में पूरी तरह से वर्णित है, जो प्रतिवादियों से संबंधित है, जिसका शीर्षक विलेख संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में न्यायसंगत बंधक के माध्यम से बैंक में जमा किया जाता है। हालाँकि, यदि प्रतिवादी 15 अप्रैल, 1980 से शुरू होने वाले 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ नियमित रूप से 1,000 रुपये प्रति माह की किश्तों के माध्यम से डिक्रीटल राशि का भुगतान करते हैं, तो वादी सामान, मशीनरी और अचल संपत्ति नहीं बेच पाएगा। ।"

---

[3] 1984 P.L.R. 382.
[4] 1991 (2) 100 P.L.R. 410.
[5] 1991 (1) 99 P.L.R. 579
[6] 1992 (1) P.L.R. 647.

वादी-बैंक, ट्रायल कोर्ट के उक्त डिक्री के साथ-साथ अनुमत ब्याज दर के साथ-साथ उसके द्वारा अनुमत किस्तों से असंतुष्ट होकर अपील दायर की। प्रतिवादियों की ओर से कोई अपील या प्रति-आपत्ति दायर नहीं की गई। अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी, हालाँकि प्रतिवादियों की ओर से कोई प्रति-आपत्ति दायर नहीं की गई थी। हालाँकि, किश्तों के संबंध में, ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस हद तक संशोधित किया गया था कि वादी-बैंक 80,000 रुपये की मूल राशि पर 6 प्रतिशत की दर से भविष्य के ब्याज के साथ प्रति वर्ष 25,000 रुपये की समान किस्त का भुगतान करेगा। 29 फरवरी 1980 से संपूर्ण डिक्रीटल राशि की वसूली तक प्रभावी। यह भी आदेश दिया गया था कि नियत तिथि पर किसी भी किश्त के भुगतान में चूक की स्थिति में, डिक्री की शेष बकाया राशि वादी-बैंक द्वारा प्रतिवादियों की चल या अचल संपत्ति की बिक्री के माध्यम से एकमुश्त वसूली की जाएगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट वादी-बैंक ने नियमित दूसरी अपील में इस न्यायालय का रुख किया। इस न्यायालय ने वादी बैंक के पक्ष में 93,347.13 रुपये की प्रारंभिक डिक्री पारित की। इसमें आगे कहा गया है कि जैसा कि आदेश 34, नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विचार किया गया है, प्रतिवादियों को डिक्रीटल राशि जमा करने या भुगतान करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। वादी बैंक को मुकदमे की तारीख से तारीख यानी 26 अप्रैल, 1984 तक डिक्रीटल राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार माना गया, जो कि बंधक ऋण के भुगतान के लिए न्यायालय द्वारा तय किया गया था। . वादी को मूलधन, ब्याज और लागत की कुल राशि पर वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार माना गया। इस फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान न्यायाधीश ने मुख्य रूप से पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड बनाम रूरा माई सोंधी और अन्य[7] मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

(17) रूरा माई सोंधी के मामले (सुप्रा) में, तथ्य इस प्रकार थे:-

(18) पंजाब एंड एसएमडी बैंक लिमिटेड, अमृतसर ने रूरा माई सोंधी और जुलुंदुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जुलुंदुर के खिलाफ बंधक संपत्ति की बिक्री से मूलधन और ब्याज के रूप में 6610.12 पैसे के लिए मुकदमा दायर किया। रूरा माई सोंधी, प्रतिवादी नंबर 1, ने ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में वादी-बैंक के पास अपना स्वामित्व विलेख जमा करके अपने घर का एक समान बंधक बनाने के बाद, 25 दिसंबर 1950 को वादी-बैंक के साथ एक ओवरड्राफ्ट खाता खोला था। . 25 जून, 1954 को, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ऋण का नवीनीकरण किया गया और उसके संबंध में एक नया प्रोनोट और अन्य दस्तावेज निष्पादित किए गए। वादपत्र में, वादी-बैंक ने 6,610.12 रुपये की वसूली के लिए एक डिक्री का दावा किया और यह राशि मुकदमे की शुरुआत की तारीख तक प्रति वर्ष 10 की सहमत दर पर गणना की गई मूल राशि और ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी प्रार्थना की गई कि मुकदमे की स्थापना की तारीख से वसूली तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज की भी अनुमति दी जाए। प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आग्रह किया कि वादी-बैंक ने मासिक छूट के साथ 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा था, जो अनुबंध दर के साथ-साथ स्वीकार्य कानूनी दर के खिलाफ था और उसने आगे की प्रार्थना पर आपत्ति जताई थी। भविष्य के ब्याज के अनुदान के लिए वादी। पक्षों की इस प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दा तय किया: -

"क्या सहमत ब्याज दर और जिस दर पर ब्याज का दावा किया गया है वह अत्यधिक है और इसका क्या प्रभाव है?"

इस मुद्दे का निर्णय वादी-बैंक के पक्ष में यह कहते हुए किया गया कि ब्याज की सहमत दर अत्यधिक नहीं थी। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने की तारीख के बाद देय राशि की वसूली तक ब्याज की अनुमति नहीं

[7] (1969) 71 P.L.R. 310

दी। वादी-बैंक ने इस न्यायालय के समक्ष पहली अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री पर हमला किया। इस न्यायालय ने प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की: -

"इस विषय पर विभिन्न प्राधिकारियों पर चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि उनका सार डी. एफ. मुल्ला द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के खंड II, 13वें संस्करण, पृष्ठ 1474 में दिया गया है। वहां यह कहा गया है।-

"..... के स्थानांतरण के तहत निर्णयों का सारांश

संपत्ति अधिनियम और आदेश 34 के तहत, यह कहा जा सकता है कि बंधक पर मुकदमे में न्यायालय ने फैसला सुनाया-

(1) ...

(2) बंधक-ऋण के भुगतान के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से मूलधन पर ब्याज, बंधक द्वारा प्रदान की गई दर पर भी.....जब तक कि दर दंडात्मक न हो, जिस स्थिति में न्यायालय उस दर पर ब्याज दे सकता है जो वह उचित समझे, या ब्याज अत्यधिक है और लेनदेन काफी अनुचित था, ऐसी स्थिति में भी न्यायालय इसे कम कर सकता है।"

(3) बंधक-ऋण के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि से वसूली या वास्तविक भुगतान की तिथि तक मूलधन, ब्याज और लागत की कुल राशि पर ब्याज, ऐसी दर पर जो न्यायालय उचित समझे। इसे न्यायालय दर पर, यानी 6 प्रतिशत प्रति वर्ष, या किसी भी दर पर अनुमति दी जा सकती है... ... ."

ऊपर उद्धृत अंश के समर्थन में कई अधिकारियों का हवाला दिया गया है। सुखराज राय बनाम रतिनाथ पंजियारा[8] में हैरिस सी.जे. और चटर्जी जे. द्वारा दिए गए पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जहां यह भी यह निर्धारित किया था-

"भले ही वादी बिहार साहूकार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर मुकदमे की तारीख से पहले ब्याज की वसूली नहीं कर सकता है, न्यायालय आदेश 34, नियम 2 और 4, सिविल प्रक्रिया संहिता, पेंडेंट लाइट ब्याज के तहत अनुदान देने के लिए बाध्य है, जैसा कि अधिनियम मुकदमे के बाद देय ब्याज से संबंधित नहीं है और न्यायालय की यह शक्ति नियम 11 से प्रभावित नहीं होती है जिसके तहत न्यायालय को इस तरह का ब्याज देने के मामले में विवेकाधिकार है लेकिन इसे अस्वीकार करने का नहीं।

पेंडेंट लाइट ब्याज देने के मामले में, आमतौर पर संविदात्मक दर की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि यह दंडात्मक या अत्यधिक न प्रतीत हो।

(19) मौजूदा मामले में, जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है, नीचे दिए गए न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि ब्याज की संविदात्मक दर अत्यधिक नहीं थी। यह भी नहीं पाया गया कि ब्याज दर दंडात्मक थी। ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाएगा कि वादी मुकदमे की तारीख से 31 जुलाई, 1959 तक डिक्री की गई राशि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की संविदात्मक दर पर ब्याज का हकदार था। , जो बंधक-ऋण के भुगतान के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि थी। वादी 31 जुलाई, 1959 से वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक मूल ब्याज और लागत की कुल राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार है।

---

[8] A.I.R. 1942 Patna 102

बेंच ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, खंड II, तेरहवें संस्करण पर मुल्ला की टिप्पणी के उद्धरणों पर भरोसा किया। मूल पाठ के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उपरोक्त टिप्पणी, तेरहवें संस्करण के लेखक ने अपनी टिप्पणियों को राजा सर मोहम्मद बनाम काजी रमजान अली[9] में प्रिवी काउंसिल के निर्णय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित किया है। सुंदर कोएर बनाम राय शाम किशन[10] । ये प्राधिकार आदेश 34 के नियम 11(बी) के संशोधन से पहले दिए गए थे, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, संहिता) में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम 66) द्वारा लाया गया था। 1956). बेंच ने 1956 के अधिनियम संख्या 66 द्वारा संशोधित संहिता के आदेश 34, नियम 11 के प्रावधानों की व्याख्या की, लेकिन उन निर्णयों पर भरोसा किया जिन्होंने असंशोधित प्रावधानों की व्याख्या की थी। बेंच को संहिता के आदेश 34 के नियम 11(बी) के संशोधित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया था, न कि असंशोधित प्रावधानों की। रूरा माई सोंधी के मामले (सुप्रा) में निर्णय एक प्रति निर्णय है क्योंकि लागू किए गए वैधानिक प्रावधानों को बेंच द्वारा नहीं लिया गया था।

(20) संहिता के आदेश 34 के नियम 11 के खंड (बी) को 1956 के अधिनियम संख्या 66 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1956 से पहले, आदेश 34 के नियम 11 के खंड (बी) के तहत, भुगतान की निर्दिष्ट तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज मूल राशि के अतिरिक्त ब्याज पर भी दिया जा सकता है। यह खंड, स्पष्ट शब्दों में, न्यायालय को खंड (ए) में निर्दिष्ट मूल राशि के योग और ब्याज पर बाद में ब्याज देने का अधिकार देता है। अधिनियम द्वारा इस खंड के संशोधन का उद्देश्य. 1956 की संख्या 66 में ब्याज पर ब्याज की अनुमति नहीं दी गई थी। अब यह केवल नियम 11 के खंड (ए) में निर्दिष्ट मूल राशियों के योग को संदर्भित करता है। आदेश 34 के नियम 11 के खंड (ए) के तहत, न्यायालय को 'ब्याज' को छोड़कर वादी को देय सभी घटक राशियों पर ब्याज देने का अधिकार है। संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आदेश 34 के नियम 11(बी) में संशोधन पेश किया गया था। संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार प्रेक्षित किया: -

"समिति का यह भी मानना है कि ब्याज पर ब्याज की अनुमति दी जानी चाहिए और इसलिए, नियम 11 के खंड (बी) को फिर से तैयार किया गया था।"

और पुनः प्रारूपित प्रावधान इस प्रकार है: -

"खंड (ए) में निर्दिष्ट मूल राशि के कुल योग पर वसूली या वास्तविक भुगतान की तारीख तक बाद के ब्याज की गणना उस खंड के अनुसार की जाएगी जैसा कि न्यायालय उचित समझता है।"

इसी आधार पर, मेसर्स नीरू प्लास्टिक मामले (सुप्रा) में दिया गया फैसला सही कानून नहीं बनाता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

मेसर्स नीरू प्लास्टिक मामले (सुप्रा) में निर्णय जे. वी. गुप्ता, जे. (जैसा कि वह तब थे) द्वारा दिया गया था। उन्होंने श्रीमती में इस निर्णय के अनुपात का पालन किया। उषा सचदेवा केस (सुप्रा)। इन दो निर्णयों का अनुसरण अशोक भान जे. ने मेसर्स एस.एम. एंटरप्राइजेज और चानन सिंह मामलों (सुप्रा) में दिए गए अपने निर्णयों में किया। विद्वान न्यायाधीश इस धारणा पर आगे बढ़े कि कानूनी रूप से वसूली योग्य ब्याज की अनुमति दी जा सकती है। संक्षेप में, श्रीमती उषा सचदेवई एस.एम. एंटरप्राइजेज और चानन सिंह मामलों में, विद्वान न्यायाधीशों ने मेसर्स नीरू प्लास्टिक्स मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के अनुपात पर भरोसा किया, जिसे हम वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पहले ही खारिज कर चुके हैं। हम गौरीशंकाई उपाध्याय के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सम्मानजनक सहमत हैं और इस न्यायालय के विद्वान

---

[9] (1920) 24 W.N. 977=58 I.C. 89
[10] (1907) 34 Cal. 150

न्यायाधीशों के संबंध में हम उपरोक्त मामलों में उनके द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं। इस पर अलग से विचार किया गया है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।

(21) ऊपर बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि वादी-बैंक लंबित ब्याज और भविष्य के ब्याज को निम्नानुसार निर्धारित करने का हकदार होगा: -

(i)- निर्णयित मूल राशि पर लंबित ब्याज देय है, लेकिन ऐसी मूल राशि पर निर्णयित ब्याज की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है;

(यदि) भविष्य का ब्याज ब्याज की संविदात्मक दर पर दिया जाएगा, और यदि ब्याज की संविदात्मक दर स्थापित नहीं है, तो उस दर पर जिस पर वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पैसा उधार दिया जाता है या अग्रिम दिया जाता है। वर्तमान मामले में, ऋण बैंक द्वारा दिया गया था और इस प्रकार यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है।

(22) परिणामस्वरूप, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री को संशोधित किया जाता है और ऊपर दिए गए निर्देशों के संदर्भ में एक नई डिक्री पारित करने के लिए मामला ट्रायल कोर्ट को भेज दिया जाता है।

(23) हमने अपील स्वीकार करते समय निर्देश दिया था कि प्रतिवादी 93,377.39 पैसे की राशि जमा करेंगे। डिक्री-धारक का वकील हमें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि राशि जमा की गई थी या नहीं। इसे ऊपर बताए अनुसार जमा नहीं किया गया है, ट्रायल कोर्ट ऊपर बताए अनुसार मूल राशि पर देय ब्याज की दर निर्धारित करेगा और उसके बाद प्रारंभिक डिक्री पारित करेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Prerna Arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh